मधुबन
MADHUBAN

हरियाणा पुलिस अकादमी का मुखपत्र

A NEWS LETTER OF HARYANA POLICE ACADEMY

website : http//www.hpa.haryanapolice.gov.in

वर्ष 10 Volume III | जुलाई-सितम्बर JULY-SEPTEMBER 2017 | अंक Issue XXXVIII

द्वितीय हरियाणा राज्य महिला पुलिस दिवस समारोह 2017

उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित महिला पुलिस मध्य में हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल तथा हरियाणा के पुलिस महानिदेशक श्री बीएस संधु भापुसे

पुलिस महानिदेशक हरियाणा श्री बीएस संधु भापुसे द्वारा मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह भेंट

हरियाणा महिला पुलिस हेतु हीरो मोटोकार्प की ओर से स्कूटर भेंटकर्त्ता श्री विजय सेठी द्वारा स्मृति पौधा भेंट

द्वितीय महिला पुलिस दिवस पर उत्कृष्ट कार्य के लिए महिला पुलिस सम्मानित

13 अगस्त को गुरु जंबेश्वर विश्वविद्यालय,हिसार में राज्य स्तरीय महिला पुलिस दिवस समारोह का आयोजन हुआ जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और हरियाणा के पुलिस महानिदेशक श्री बीएस संधु,भापुसे, पुलिस व प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी व गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। विभिन्न जिलों से महिला पुलिसकर्मियों, महिला पुलिस स्वयंसेविकाओं ने भी भाग लिया।

इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने पुलिस एवं जनकल्याण के लिए अनेक योजनाओं की घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने व महिला प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए महिला पुलिस की स्पेशल बटालियन बनाई जाएंगी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने हिसार में प्रदेश का पहला महिला पुलिस प्रशिक्षण केंद्र खोलने और पश्चिम ग्ररुग्राम और फरीदाबाद एनआइटी में भी एक-एक महिला थाना खोलने की घोषणा की। इससे गुरुग्राम और फरीदाबाद में महिला थानों की संख्या तीन-तीन हो जाएगी। इसके अलावा पुलिस जिला हांसी और दादरी सहित नारायणगढ़, गोहाना, बल्लभगढ़ और मानेसर में भी महिला थाने खोले जाएंगे। उन्होने कहा कि साल 2014 में महिला पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या छह फीसद थी। मौजूदा समय में यह बढ़कर 9 फीसद हो गई है। सरकार का लक्ष्य इसे 10 फीसद तक ले जाना है। इसके मद्देनजर सरकार जल्द ही एक हजार महिला पुलिसकर्मियों की भर्ती करने जा रही है। मुख्य अतिथि ने कहा कि कई मामलों में महिलाओं की शिकायतें झूठी पाई जाती है। ऐसे में महिलाओं की प्रताड़ना के शिकार पुरूषों के लिए भी महिला थाने खुले हैं। कई मामलों में महिलाओं की शिकायतें झूठी पाई जाने की रिपोर्ट पर उन्होंने कहा कि पीड़ित महिलाओं को न्याय प्रदान करने लिए महिला थानों को खोला गया है। झूठी शिकायत पर किसी को प्रताड़ित करने के लिए नहीं । मुख्यमंत्री ने सभी महिलाओं को 33 फीसद आरक्षण की अपेक्षा 50 फीसद आरक्षण देने की वकालत की।

मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में कहा कि प्रदेश के सभी महिला थानों में महिला पुलिसकर्मियों के बच्चों की देखभाल के लिए विशेष क्रेच खोले जाऐंगे।

उन्होंने उत्कृष्ट कार्यों के लिए 'मुख्यमंत्री महिला सर्वोत्तम सेवा पदक' भी प्रदान किए। महिलाओं को कानून एवं अधिकारों की जानकारी देने,शिक्षण संस्थानों में छात्राओं को जागरूक करने सहित अन्य कार्यों के लिए पुलिस अकादमी मधुबन की आईजी डा.सुमन मंजरी भापुसे को, नेपाल व चीन की तरफ से माऊंट एवरेस्ट फतह करने पर हिसार की एसआई अनीता को, प्रथम महिला पुलिस राइडर महिला थाना फतेहाबाद की सिपाही सुंदर कुमारी को, अद्वितीय कर्त्तव्यनिष्ठा के लिए महिला थाना फरीदाबाद की सिपाही बिमलेश को और महिला विरूद्ध अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए पंचकूला की एसआई सोमवती को सम्मानित किया गया। इस मौके पर हीरो मोटो कार्प की ओर से प्रदेश के महिला थानों के लिए 100 स्कूटर भेंट की गई जिन्हें मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

जीवन का सबसे बड़ा वरदान है आजादी: केके सिंधु

आजादी की 70वीं वर्षगांठ पर 15 अगस्त को हरियाणा पुलिस अकादमी का हर्षवर्धन सभागार देश प्रेम की भावना से सराबोर हो झूम उठा। यह अवसर था डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल मधुबन के बच्चों द्वारा स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने का। मुख्य अतिथि श्री के के सिंधु, भापुसे, पुलिस महानिदेशक मधुबन परिसर ने दीप प्रज्वलित करते हुए आजादी के इस उत्सव का शुभारंभ किया। उन्होंने बच्चों को शुभ संदेश देते हुए अपने संबोधन में कहा कि

आजादी जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। प्रकृति द्वारा यह वरदान मनुष्यों सहित सभी जीवों को दिया गया है। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि वरदान अपने साथ जिम्मेदारी भी लेकर आता है। धर्मशास्त्रों और इतिहास में अनेक उदाहरण ऐसे हैं जो यह बताते है कि यदि वरदान को जिम्मेदारी के साथ ग्रहण नहीं किया जाता तो उसके अभिशाप बनने में देर नहीं लगती है। आजादी के कारण प्राप्त होने वाली सुविधाओं के बदले में हमारे भी कुछ दायित्व हैं जिन्हें हमें निभाना चाहिए। हमें देश की आजादी को बनाए रखने और देश को मजबूत करने के लिए हमेशा पहल करनी चाहिए। हम सही मायने में आजाद हैं यदि हम स्वेच्छा से आगे बढ़कर उन कार्यों को करने के लिए तत्पर रहते हैं जो देशहित में होते है और उन कार्यों की रोकथाम करते है जो देश हित में नहीं है। आजादी के असंख्य मतवालों ने भारत माता को आजाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। उनके बलिदान के फलस्वरूप ही आज हम एक स्वतंत्र देश के नागरिक हैं। स्वतंत्रता दिवस इन महान सपूतों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने का भी अवसर है। वर्तमान समय में आजादी के लिए प्राणों की आहुति देना ही आवश्यक नहीं है। हम अपने छोटे -छोटे कार्यों से भी आजादी में योगदान दे सकते हैं। उन्होंने बच्चों से कहा कि जीवन में हमेशा सच्चाई के साथ रहें। अनावश्यक बिजली जलते हुए देखें तो बटन बंद कर दें, पानी बह रहा है तो नल को बंद कर दें, गन्दगी न फैलाये न फैलाने दें, पोलिथीन जैसी हानिकारक वस्तुओं के इस्तेमाल से बचे, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, समाज में मिल-जुल कर रहें, सड़कों, अस्पतालों आदि सार्वजनिक स्थलों पर अनुशासित होकर चलें। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति अपने छोटे-छोटे योगदान से बेहतर नागरिक बनकर देश के नव-निर्माण में योगदान दे सकता है और आजादी के मतवालों के प्रति सच्चा सम्मान व्यक्त कर सकता हैं। श्री सिंधु ने देशभक्ति से ओत-प्रोत प्रस्तुतियों के लिए बच्चों की भूरी-भूरी प्रशंसा की।

स्कूल की प्राचार्य श्रीमती अनिता गौतम ने इस अवसर पर श्री सिंधु का स्वागत व आभार व्यक्त किया तथा सिंधु को उनके जन्मदिन (15 अगस्त) पर स्कूल की ओर हार्दिक बधाई दी। कार्यक्रम में अकादमी के पुलिस अधीक्षक श्री विनोद कौशिक भापुसे, हरियाणा पुलिस आवास निगम के कार्यकारी अभियन्ता श्री संजीव वर्मा सहित परिसर निवासी पुलिस अधिकारी, स्टाफ व अभिभावक उपस्थित रहे।

हर घर हरियाली हरियाणा में खुशहाली: केके सिंधु

मधुबन पुलिस परिसर में वन-महोत्सव का आयोजन

12 जुलाई गुरुवार को मधुबन पुलिस परिसर में वन महोत्सव का आयोजन किया गया जिसका मुख्य अतिथि के रूप में पुलिस महानिदेशक श्री के के सिंधु, भापुसे ने पौधारोपण से शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि हर घर हरियाली तभी होगी हरियाणा में खुशहाली, यह नारा नहीं आज के समय की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि बदलते वातावरण में कम होता पानी और बढ़ती घुटन अपराध के नए स्वरूप को जन्म देगी। स्वच्छ वातावरण और स्वस्थ समाज के हित में हम सभी को मिलकर पेड़ों का संरक्षण व संवर्धन करना है। इस अवसर पर पुलिस महानिरीक्षक डा. सुमन मंजरी, भापुसे ने कहा कि तेजी से बढ़ता मरूस्थल हरियाणा की धरती को भी मरूस्थल बना देगा। अब किसानों को भी बदलते मौसम के मिजाज को देखते हुए फसल चक्र बदलना होगा। पुलिस महानिरीक्षक श्री शिवास कविराज, भापुसे ने कहा कि यदि मानव जाति ने प्रकृति संरक्षण के व्यवहार को जीवन की संस्कृति नहीं बनाया तो भविष्य में तीसरा, विश्व युद्ध पानी के संकट पर होगा। कार्यक्रम के संयोजक जिला वन अधिकारी श्री बिजेन्द्र सिंह ने कहा कि हरियाणा के समस्त विभाग मिलकर हरियाणा वन क्षेत्र को बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। उन्हें उमीद है कि ऐसे ही प्रयासों से हरियाणा की हरियाली के क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी। वन महोत्सव मधुबन में डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल मधुबन की छात्र-छात्राओं ने गीतों व नुक्कड नाटक के माध्यम से पर्यावरण और वन संरक्षण का संदेश दिया। बच्चों की शानदार प्रस्तुतियों ने दर्शकों को भाव विभोर कर दिया। स्वागत श्री ओमवीर सिंह, भापुसे आदेशक चतुर्थ वाहिनी ने किया। धन्यवाद ज्ञापन श्री नृपजीत सिंह, भापुसे पंचम वाहिनी ने किया। इस अवसर पर उप पुलिस अधीक्षक अकादमी श्री नारायण चंद हपुसे, उप पुलिस अधीक्षक भूप सिंह गुलिया हपुसे हरियाणा सशस्त्र पुलिस, उप पुलिस अधीक्षक श्री कृष्ण कुमार हपुसे हरियाणा सशस्त्र पुलिस, उप पुलिस अधीक्षक श्री अशोक कुमार हपुसे हरियाणा सशस्त्र पुलिस व डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल मधुबन की प्राचार्य श्रीमती अनिता गौतम व प्रशिक्षणार्थियों सहित स्टाफ भी ने भी वन महोत्सव में भाग लिया और पौधारोपण किया।

सेव द चिल्ड्रन और हरियाणा पुलिस अकादमी ने जेंडर आधारित हिंसा को रोकने हेतु उठाए कदम

मधुबन में कार्यशाला में लिया 700 पुलिसकर्मियों ने भाग

21 जुलाई को हरियाणा पुलिस अकादमी मधुबन और स्वयं सेवी संस्था सेव द चिल्ड्रन द्वारा यूएस दूतावास की सहायता से अकादमी के हर्षवर्धन सभागार में कार्यशाला का आयोजन किया गया। जेंडर आधारित हिंसा के प्रति संवेदीकरण हेतु इस कार्यशाला में 700 पुलिसकर्मियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारम्भ अकादमी की महानिरीक्षक डा. सुमन मंजरी, भापुसे ने किया। रिसोर्स पर्सन मेजर डा. मीता सिंह ने प्रतिभागियों को जेंडर आधारित हिंसा को समझने व रोकथाम के बारे में जानकारी दी।

मुख्य अतिथि डा. मंजरी ने अपने संबोधन में कहा कि जेंडर आधारित हिंसा की रोकथाम करने में समाज के साथ पुलिस की भी महत्वपूर्ण भुमिका है। पुलिस के पास महिला शिकायतकर्ता, गवाह या अपराधी जिस भी हैसियत से आए उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अच्छा व्यवहार वही है जिसकी अपेक्षा आप अपने लिए करते हैं। इसलिए सामने वाले की परिस्थिति में स्वयं को रखकर किया जाने वाला व्यवहार अच्छा व्यवहार साबित होगा और आपकी छवि बेहतर बनेगी। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग भारी कार्य बोझ व प्रतिकूल परिस्थितियों मे कार्य करता है। चूंकि पुलिस का कार्य हमने स्वेच्छा से चुना है इसलिए पेशेवर कौशल रखने वाले पुलिसकर्मी अधिक काम के बोझ का बहाना नहीं बनाते। वे समाज को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए सदैव तत्पर रहते है। पिछले कुछ सालों से समाज में महिलाओं की उपस्थिति तो बदली है,अब अधिक महिलाएं नौकरियों पर दिखाई देने लगी है लेकिन उनकी स्थिति नहीं बदली है। उन्होंने कहा कि बदलाव के लिए व्यक्ति की सोच को बदलना आवश्यक है और इस प्रकार की कार्यशालाएं व्यक्ति की सोच में परिवर्तन लाने मे सहायक होती हैं। उन्होंने अकादमी के निदेशक व डीजी मधुबन परिसर श्री केके सिंधु, भापुसे और अकादमी की और से 'सेव द चिल्ड्रन' संस्था का स्वागत और आभार भी व्यक्त किया।

कार्यशाला में सेव द चिल्ड्रन की रिसोर्स पर्सन मेजर (डा.) मीता सिंह ने जेंडर आधारित हिंसा पर अपने विचार रखते हुए कहा कि लड़कों की परवरिश के दौरान ही उनमें भावनाओं और संवेदनाओं का दमन करने की आदत डालने का प्रयास किया जाता है जैसे कि प्राय: कहा जाता है कि लड़के नहीं रोते। इस प्रकार आंसू के रूप में उनकी संवेदनाओं को बाहर आने से रोका जाता है जो बाद में हिंसा के रूप में फूटते हैं। उन्होंने कहा कि जेंडर आधारित हिंसा से पुरुषों का भी बड़ा नुकसान हो रहा है। जेंडर आधारित भेदभाव के चलते पुरुषों पर अपने पौरूष को स्थापित करने के लिए इतना दबाव होता है कि वे अपने सामान्य कार्य भी सहज रूप से नहीं कर पाते हैं। प्रभाव कायम रखने के लिए महिलाओं और बच्चों के प्रति उनका व्यवहार क्रूरता का रूप ले लेता है। उन्होंने हिंसा को रोकने के लिए समाज की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा कि बचपन से ही बच्चों को भेदभाव मुक्त परिवार और माहौल मे बड़ा किया जाना चाहिए। उन्होंने महिला व लड़कियों के प्रति हिंसा की रोकथाम के लिए बने कानून व प्रक्रिया के बारे में भी प्रतिभागियों को जानकारी प्रदान की।

इससे पूर्व सेव द चिल्ड्रन संस्था के परियोजना निदेशक श्री जतिन मोंदार ने संस्था के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि यह संस्था विश्व के 120 देशों में, भारत के 20 राज्यों में बच्चों के संरक्षण के लिए कार्य कर रही है। 'आवाज उठाएं और महिलाओ- लड़कियों के प्रति हिंसा रोकें', परियोजना के तहत हरियाणा, पंजाब, राजस्थान व उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से कार्य कर रही है। संस्था के परियोजना प्रबन्धक श्री सिद्धार्थ पांडे ने हरियाणा और देश के संदर्भ में बच्चों और महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा संबन्धी मामलों के बारे में आंकड़े प्रस्तुत किए। कार्यक्रम का संचालन परियोजना संयोजक श्री प्रतीश कुमार तिवारी व उप निरीक्षक रामकुमार ने किया।

इस अवसर पर अकादमी के उप पुलिस अधीक्षक श्री नारायणचंद, श्री महेश कुमार, निरीक्षक रामपाल, सुमेर सिंह, रविंद्र सिंह व अकादमी का स्टाफ भी उपस्थित रहा।

आशा स्कूल मधुबन में मनाया नवरात्र उत्सव

27 सितम्बर को मधुबन पुलिस परिसर आशा स्कूल के दिव्यांग बच्चों द्वारा माता रानी के 'नवरात्रों' के अवसर पर नवरात्र सप्तमी दिवस बड़ी धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। दिव्यांग बच्चों ने स्कूल प्रांगण की सुंदर सजावट की और सप्तम नवरात्र दुर्गा स्वरूप माता कालरात्रि की आरती की इस के बाद संगीत की धुन पर डांडिया नृत्य की शानदार प्रस्तुति के साथ उपस्थित जनों का मन मोह लिया। माता रानी के भजनों से स्कूल परिसर भी आनंदमय हो उठा।

इस अवसर पर मुख्यातिथि समाजसेविका आलोका कविराज ने कहा कि नवरात्र के पावन दिनों में प्रत्येक दिन मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की पूजा-अर्चना की जाती है। प्रथम नवरात्र दुर्गा स्वरूप माता शैलपुत्री, द्वितीय नवरात्र दुर्गा स्वरूप माता ब्रह्मचारिणी, तृतीय नवरात्र दुर्गा स्वरूप माता चन्द्रघण्टा, चतुर्थ नवरात्र दुर्गा स्वरूप माता कूष्माण्डा, पंचम नवरात्र दुर्गा स्वरूप स्कन्दमाता, षष्ठम नवरात्र दुर्गा स्वरूप माता कात्यायनी, सप्तम नवरात्र दुर्गा स्वरूप माता कालरात्रि, अष्ठम नवरात्र दुर्गा स्वरूप माता महागौरी और नवम नवरात्र दुर्गा स्वरूप माता सिद्धिदात्रि की अराधना की जाती है। माता दुर्गा, शक्ति का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि विशेष बच्चों को इस प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से भारतीय संस्कृति से परिचित कराया जाता है इसकी उन्हें अतिप्रसन्नता है। बच्चों को इस प्रकार के उत्सवों में शामिल करते हुए हम इनका व्यवहारिक व बौद्धिक विकास कर सकते हैं। तीज - त्यौहारों को दिव्यांग बच्चों के साथ मनाये जाने से इन्हें ये त्यौहार सालों तक याद रहेंगे और नव उर्जा प्रदान करेंगे। मुख्य अतिथि महोदया ने सभी बच्चों को फल व मिठाई का प्रसाद वितरित किया। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि हरियाणा सशस्त्र पुलिस मधुबन के द्वारा दिव्यांग बच्चों के लिए 'आशा स्कूल' चलाया गया है जो एक सराहनीय पहल है और पुलिस के मानवीय पक्ष को मजबूत करती है। उन्होंने इस प्रयास के लिए पुलिस अकादमी के निदेशक श्री केके सिंधु व हरियाणा सशस्त्र पुलिस के महानिरीक्षक श्री एचएस दून व अन्य सभी सहयोगी अधिकारीयों व कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर स्कूल इंचार्ज नरसिंह, स्कूल शिक्षिका काजल, सुनीता,दर्शना, मुख्य सिपाही संजय पोरिया, अजय, रणबीर सिंह, प्रेम सिंह, गणेश व स्कूल स्टाफ के सदस्य उपस्थित रहे। स्कूल के बारे में जानकारी हेतु **www.ashafoundation.info** पर भी लॉग-इन किया जा सकता है।

नशा पूरे समाज को करता है दुष्प्रभावित - राजेश कुमार

14 सितम्बर: नशा पूरे समाज पर बुरा प्रभाव डालता है, इसकी रोकथाम के लिए प्रत्येक नागरिक को आगे आना चाहिए। यह विचार हरियाणा पुलिस अकादमी के जिला न्यायवादी श्री राजेश कुमार ने नशीले पदार्थों की तस्करी रोकथाम विषय पर आयोजित विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए व्यक्त किए। अकादमी के हर्षवर्धन सभागार में हुए इस कार्यक्रम में राज्यभर से 200 पुलिसकर्मियों ने भाग लिया।

श्री राजेश कुमार ने प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि 1988 में नशीले पदार्थों के अवैध तस्करी की रोकथाम कानून अस्तित्व मे आया है जिसमें कानून लागू करने वाली ऐजेंसियों को महत्वपूर्ण अधिकार दिए गए हैं। इस कानून के तहत तस्करी में संलिप्त व्यक्ति को 5 दिन के लिए बिना कारण बताए रोककर रखा जा सकता है। संयुक्त सचिव पद के अधिकारी के आदेश से ऐसे व्यक्ति को 1 साल तक के लिए निरुद्ध किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कानून के साथ-साथ नशे के खिलाफ सामाजिक जागरूकता भी जरूरी है। उन्होंने नशे के दुष्प्रभावों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि वर्तमान में 67 में से 1 घर का कोई न कोई सदस्य नशे का शिकार है। नशा करने वाले 10 में से 2 व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी उम्र 16 साल से कम है। उन्होंने कहा कि अफीम, हेरोइन, समैक आदि नशीले पदार्थों का सेवन करने वाले 50 प्रतिशत लोग पहले शराब से नशे की शुरूआत करते हैं और बाद में गंभीर नशे का शिकार हो जाते हैं। नशा केवल व्यक्ति की सेहत ही खराब नहीं करता बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी खराब करता है। नशेड़ी अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए निजी और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं। वे सड़क पर लगे खंभो, ग्रिलों व रेल की पटड़ी से लोहे के नट-बोल्ट चुराकर लोगों के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं। उन्होंने प्रतिभागियों से अपील करते हुए कहा कि पुलिस और नागरिक के रूप में वे अपनी-अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं और नशा मुक्त समाज का निमार्ण करें। कार्यक्रम में एफएसएल मधुबन की वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी डा. नीलम आर्या ने अफीम, भांग, कोका से बनने वाले नशीले पदार्थों की पहचान और नशीले पदार्थ होने के लिए कानूनी शर्तों के बारे में जानकारी दी। अकादमी के प्रशिक्षक श्री बलबीर सिंह ने एनडीपीएस कानून के तहत तफतीश, गिरफतारी, माल को कब्जे में लेने की तकनीकों के बारे में बताया। प्रतिभागियों ने कार्यक्रम के प्रश्नकाल में सक्रिय भागीदारी की।

सामाजिक सुरक्षा मुद्दों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन

27 से 29 सितंबर तक राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान नई दिल्ली के तत्वावधान में हरियाणा पुलिस अकादमी मधुबन द्वारा सामाजिक सुरक्षा विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में अराजपत्रित पद के 40 पुलिस अधिकारियों ने भाग लिया। अकादमी व संस्थान की भागीदारी में यह तीसरा प्रशिक्षण कार्यक्रम था। कार्यक्रम का शुभारम्भ हरियाणा पुलिस अकादमी की महानिरीक्षक डा. सुमन मंजरी भापुसे ने सामाजिक सुरक्षा मामलों में पुलिस की भूमिका विषय पर अपने व्याख्यान से किया।

कार्यक्रम के प्रथम दिन कैथल के एडवोकेट श्री अरविंद खुरानिया द्वारा सामाजिक सुरक्षा से सबंधिंत संवैधानिक प्रावधानों और संसद द्वारा किए गए प्रयत्नों के बारे में, हरियाणा सशस्त्र पुलिस अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी डा. कार्तिक दुआ द्वारा नशा खोरी के दुष्प्रभाव व रोकथाम, एचआईवी एड्स व पुनर्वास विषय पर जानकारी दी गई। द्वितीय दिवस को जिला उपभोक्ता अदालत कुरूक्षेत्र के पूर्व अध्यक्ष डा. एएन मनोचा एडवोकेट ने सामाजिक सुरक्षा के संबंध में न्यायपालिका की भूमिका, करेक्शनल लॉ, अपराधों से होने वाली मानवीय सामाजिक और आर्थिक हानि के बारे में तथा दोपहर बाद के सत्र में मानव दुर्व्यपार की रोकथाम के क्षेत्र में सक्रिय गैर-सरकारी संस्था शक्ति वाहिनी के अध्यक्ष श्री रविकांत श्रीवास्तव एडवोकेट द्वारा मानव दुर्व्यपार की समस्या इसकी रोकथाम और इससे प्रभावित के पुनर्वास में पुलिस, अभियोजक, न्यायालय, चिकित्सा, शिक्षण संस्थानों, ग्राम पंचायतों, स्थानीय निकायों, गैर-सरकारी संस्थाओं, सामाजिक सशक्तीकरण विभाग जैसे हितधारको की भूमिका पर प्रकाश डाला।

कार्यक्रम के अन्तिम दिवस पर हरियाणा पुलिस अकादमी के उप जिला न्यायवादी श्री रामपाल ने वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा, वरिष्ठ नागरिकों के लिए आश्रय स्थलों, नशा मुक्ति केन्द्रों तथा सामाजिक सुरक्षा योगदान देने वाली ऐजेंसियों के बारे में प्रतिभागियों का ज्ञानवर्धन किया। सीबीआई दिल्ली के सेवानिवृत्त उप महानिरीक्षक श्री ओपी छतवाल ने भिक्षावृती के कारणों, इसकी रोकथाम के लिए बने कानून व व्यूहरचना और इसकी रोकथाम हेतु पुलिस द्वारा किया जाने योग्य हस्ताक्षेप के बारे में मार्गदर्शन किया। एक अन्य सत्र में उन्होंने अपराधिक समस्या पर आधुनिक दृष्टिकोण विजन 2020 और भीख, दासत्व के संबंध में वैधानिक विचार पर प्रतिभागियों को जानकारी दी। अकादमी के उप जिला न्यायवादी श्री बलजीत सिंह ने मीडिया की भूमिका के संबंध में तथा अकादमी के जिला न्यायवादी श्री राजेश कुमार ने सामाजिक सुरक्षा की प्रकृति क्षेत्र व सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता पर अपना व्याख्यान रखा। प्रतिभागी पुलिस अधिकारियों ने कार्यक्रम को वैचारिक रूप से उन्हें उन्नत करने वाला तथा पुलिसिंग में मानवीय पक्ष को मजबूत करने में उपयोगी बताया। कोर्स संयोजक श्री रामपाल उप जिला न्यायवादी अकादमी ने अतिथि वक्ताओं तथा राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान नई दिल्ली का आभार व्यक्त किया।

Insight Into Police Working

by Dr. Sarita Malik, HCS (Ph.D. M.A. Psychology, B.A. L.L.B.)

Police thy name instills fear, anger, anxiety & kind of amusement when bulging tummy over their uniforms is seen. The strength of a democracy and the quality of life enjoyed by its citizens are determined in large measure by the ability of the police to discharge their duties. The police detects, fights and controls the enemies (both the visible and also invisible) of the public and society at large *(Philip, 1996)*. As such police personnel face dangerous situations as part of their daily routine.

In the Indian context, it is indeed quite surprising that there is no definition of the police in the fundamental enactments concerning the police force including the main Act of the statute book that is the Police Act, 1861. However, the powers and duties of police officers/ policemen are described at length in the Police Act, 1861 and the Rules framed thereunder. As per the Haryana Police Act, 2007, the term "police officers" is defined in Section 2 (j) as follows: *"Any member of the police service of the State constituted under this Act and includes Indian Police Service (IPS) officers of the state cadre."*

Although policing is a very vital aspect for the existence of a society yet the police force as a whole is the target of criticism by all and sundry, including intellectuals, jurists, social activists, media, politicians and citizens.

Many people believe that the police at times shield criminals, refuse to register complaints, fabricate false cases against innocent victims and frequently resort to "padding & illegal" detentions at police stations *(Singh & Singh, 2008).*

According to R. Choudhary (2009) a serious role conflict always exists in policing more specifically between ideals of crime control and ideals of due process. Limitations of our criminal justice system hamper efficient and effective functioning of police and there also prevails an attitude in the society which judges the police effectiveness on the basis of achievement of goals and its outcomes. The situation becomes more complex as the prevailing core police sub culture makes police officers think that there are only little fighters, no one else understands them, they are loyal to each other, they can fight crime only by bending the rules and that public is by and large too demanding and unsupportive. Further, police resorts to extra judicial methods during investigation as there are inadequacies in the relevant legislations, increase and changing nature in the crime, too much expectations of the public from the police.Thus, police today is viewed as beleaguered institution which has lost a clear sense of identity.

Likewise, there are certain glaring examples which portray police brutality such as the merciless lathi charge on the empty handed Honda workers in Gurgaon "Now Gurugram" on 25 July, 2005 which was highlighted by several T.V. channels and it telecasted the police highhandedness live.These are instances of police bestiality. Moreover, Custodial crimes, including rapes, murders etc. are a routine phenomenon for the police in India. For want of sincerity & sensitivity on the part of police not only the law and order situation has suffered but also the overall performance of police has come under severe fire *(Singh & Singh,2008)* (may include some All India Cases i.e., Nirbhaya & Talwar cases of Noida).

Its an irony that the faith from our Indian Police has been uprooted by the Government and Public at large. Whenever, the State is faced with communal disturbances, any heinous crime and other law & order problems, paramilitary and Armed forces are called upon for aid to civil power very frequently, thus diluting the functions of our Indian Police System and thereby further demotivating and dehumanizing them.

Public at large has no faith in police, even if the public is stopped for over-speeding, the reaction of public while talking to policemen is so sharp and blunt as if policemen has done a fault in stopping them and whereas the lawbreaker is on the right path.

PROBLEMS FACED BY POLICE

a) Although, India today is the world's largest democracy, the police in India are still imbued with a ruler-supportive ethic - one that encourages the police to do the bidding of the political leadership rather than to stand as impartial guardians of the people's democratic rights *(Dhillon, 1998).*

b) On many occasions the decision to arrest is made on political considerations rather than as a means to deal with the crime phenomenon *(Raghavan, 1999; Singh, 1999).* Large scale transfers and postings of officers of all ranks and the inability of the police leadership to discipline officers who are politically connected all present evidence of a police department that is ruled by political expediency rather than any established procedures and norms *(Verma, 2000).*

c) Lack of functional autonomy and absence of an environment that encourages living up to ideals pushes a police officer towards a state of apathy. Simultaneously, absence of direct accountability to people pulls them towards corrupt practices.

d) In a study by Deb, Chakraborty, Chatterjee & Srivastava (2005) found in a study on Kolkatta traffic police that the major problems faced by them while discharging their responsibilities were anxiety due to tense situation 62.5%, followed by unnecessary case pressures 44.6%, political pressure and interference 42.8%, lack of manpower 41.1%, pressure from discharging duties 32.14%, non-cooperation from the public 30.36%, lack of infrastructure 26.8% and non-cooperation from higher authorities 17.9%.

e) The police departments are also poorly funded, and all material acquisitions have to be procured by seeking government grants tailored to a specific need and only a limited amount is provided for general maintenance of vehicles, buildings, communication equipment and uniform & stationary etc.There are regional differences in resources and working conditions but the system is uniform and police functions,

responsibilities, organization and training remain comparable across different States *(Verma & Gavirneni 2006).*

f) **Glaringly, human rights of police officers are at times infringed. According to Tandon (2007), police officers are Government servants who are, in principle, entitled to the same human rights as any other citizen. They do not give up their basic rights by signing up to the police services. Humane conditions of work are the key to efficient and effective working of the policemen. However, the overall work environment of police, particularly of subordinates and middle rank officers is dehumanizing and deintellectualizing. Ironically, the police personnel who are obliged to protect and uphold the human rights of others are themselves the victims of the violation of their human rights in the form of undue long working hours, leave problems, denial of family life, denial of social life, delayed promotions, inadequate infrastructure, poor salaries etc. Securing their human rights will undoubtedly enable them to protect, help and reassure the citizens in a better way.**

g) The service conditions of the police persons, especially those of the Constabulary are poor and unsatisfactory. According to Malik (2004), constables are junior most officials and are the most important link in the police chain. The police can never succeed if they are not educated, intelligent and properly trained to discharge their duties sincerely. The Britishers expected of them only to protect them and their property. The result was that though the number of policemen multiplied, their educational and training standards and public dealings remained more or less the same.

When India is enjoying Diwali & Holi they stand to save the nation from injury, riots etc. The average working hours of a police person are much more than other government servants as no fixed duty hours are there. A policeman often has 24-hour workday and hardly gets any time for his family, which affects his work profile and efficiency. Moreover, they get limited number of holidays and they are seldom permitted to avail them as per their familial requirements. The leave utilization analysis showed that police personnel utilized only 52 percent of the total leave entitlements compared to 95 percent for a normal government employee *(Singh & Singh, 2008).*

The pay and allowances of the constabulary are very meager and the speedy increase in inflation rate has made their position more deplorable. Further, inadequate chances of promotion and overwork in the department due to shortage of staff also add to their frustration and anger as the environment in which the police is working is not congenial. The constabulary, which constitutes 80 percent of the country's total police force, is ill-equipped and poorly paid. Moreover, the ever increasing demand for VVIP/VIP security causes a big drain on meagre police resources.

Also, health and hygiene problems are seen in police officers to a great degree for example high blood pressure, heart problems and tuberculosis are witnessed more in the Police Department as compared to other departments. Further, the living conditions of the police personnel in barrack is yet another problem. Most of the police stations are usually housed in old and dilapidated buildings.These outmoded police stations are deficient in basic amenities like drinking water, lights and fans, toilets, etc *(Singh & Singh, 2008).*

New laws are enacted with a rapid pace without involving the police in the conception stage, with the result that the implementation of these laws leaves much to be desired. Further, the accused is presumed to be innocent and the burden is on the prosecution to prove beyond reasonable doubt that he is guilty *(Section 101 of the Indian Evidence Act).* Our criminal law has several provisions which breathe a distrust of the police. Sections 161 and 162 of the Code provide that the statements of the witnesses examined during investigation are not admissible and that they can only be used by the defence to contradict the maker of the statement. The statement made by the accused before a police officer is also not admissible as evidence *(Section 25 of Indian Evidence Act).* The statements recorded at the earliest stage normally have greater probative value but cannot be used as evidence. The observations of the courts in several criminal cases show that the judges are reluctant to accept the testimony of police officers. The delayed court trials to produce the desired deterrence acts as a severe limitation on the success of the police in containing crime.

Khan & Bhandari (2006) opine that police perform not only crime prevention and detection in their role, but also perform many service functions, for example, giving directions, taking sick people to hospitals, mediating family disputes, and so on. These do not necessarily result in a crime or in arrests. The service aspect of the police role is yet another function by which the public judges the police.

Moon & Zager (2007) in a study on 434 Korean police officers examined the effects of individual factors, organizational factors, and beat characteristic variables on officers' attitudes toward citizen support. It was found that the seniority and the level of the police department were significantly related to officers' attitudes toward citizen support. Senior officers were more likely to have positive attitudes toward citizen support. The study found that a majority of Korean police officers perceived that citizens do not support the police. These findings suggest that distrust and antagonism between the police and citizens was deep-rooted in the minds of the Korean police.

Police face many challenges in the modern era as crime has taken a new face in recent times. Crimes like the drugs, illegal human trafficking, wildlife crimes, intellectual property, financial frauds and cyber crimes have international implications. The era of globalization has not only increased the reach and opportunities for organized crime but has lead to coming together of their networks and resources.Thus, focus of police in future shall be on the international crime and perhaps may also be defined by it R. Choudhary, (2009).

Although other institutions and the economy have been rapidly integrating into the world system yet the Indian police have failed to keep pace with the rapid changes. Even police forces throughout the world are currently being asked to respond to an ever growing list of new demands and responsibilities. Thus, the Indian police has no choice

but to embrace the much needed changes.

Today, police is also change oriented. According to R. Choudhary (2009), recently police has started outsourcing its own duties in the following ways such as: constitution of village defence committees for prevention of crime, development and constitution of neighborhood watch and ward machinery for collection of Intelligence, licensing to private security firms for providing security to public sector undertaking and private entrepreneurs etc., outsourcing the police like hiring of private detectives and civilian staff for surveillance, transpotation and other police tasks.

` Hence all these problems eclipse the ferformance of police functionaries and they become the targets of criticism.

Several Committees have been set up over the years, those have made practical recommandations for police reforms but unfortunately they have not been implemented.

Hon'ble Supreme Court pronounced a historical judgment on 23rd September, 2006 for reforming the criminal justice system and strengthening the rule of law in the country for making police administration more accountable and to protect it from political interference. Hon'ble Apex Court taking into the account the recommendations of the National Human Rights Commission, the Julio Riberio Committee and the Soli Sorabjee Committee, virtually overhauled the Indian Police Act, 1861. Some of the recommendations of the Committee are summed up below:-

1. Setting up of a State Security Commission in every state to ensure that state government does not exercise unwarranted influence or pressure on the police.
2. DGP of state to be selected from among three senior-most officers; will have fixed tenure of atleast 2 years.
3. IG, Deputy IG, SP and SHO will have minimum fixed tenure of 2 years.
4. Investigating police will be separated from law and order police to ensure speedier investigation, between expertise and improved rapport with people.
5. Police Establishment Board in each state to decide on transfers, postings etc. and service related matters of officers' upto DSP.
6. Police Complaints Authority at district level to look into complaints against police officers till DSP.
7. Center to set up National Security Commission for selection and placement of Chiefs of Central Police Organizations.

The Court ordered that the Centre and the State shall make earnest efforts to implement the orders and to draft a Police Act. However, it is only political will which is coming in the way of implementation of the reforms. The Haryana Government has recently enacted The Haryana Police Act, 2007 *(Haryana Act 25 of 2008)* to comply with the Supreme Court orders. Thus, Hon'ble Apex Court has done a valuable service to the nation for bringing about sweeping reforms in the age old Police Act of 1861. However, it is up to the implementing agency to see how to implement it in letter and spirit. In a hard hitting article in The Tribune, "Short cuts won't do: States diluting Supreme Court fiat on police reforms". Eshwar Anand (2009), has lamented that most states have resorted to short cuts and left many loopholes in their legislations which is a great disservice to the police and the people.

Many States have made their own Police Acts to implement recommendation of Hon'ble Apex Court yet the reality is that its just on paper & gathering dust & still transfers & investigations are flaunted by politicians & not rules by the Police Act so formed.

However, the implementation on the judgment of Hon'ble Supreme Court on police reforms as pronounced on September 26, 2006 still remains a far cry even after more than a decade in most of the States.

The policing system needs overhauling and still as on date there is no bifurcation of different police wings i.e., investigation, law & order.

Inadequacy of Police strength at every level leads to overburden/stress and strain on our Indian Police Personnel who wear those uncomfortable shoes and belts for 24 hours and there is no respite to them. Thus, their uniforms need to be more human friendly to bear that duty strain. Moreover, there is an urgent need to introduce humane working hours so as to mitigate the level of stress amongst Police Personnel. At the same time, police commanders at all levels need to equip themselves with welfare orientation schemes and implement the same.

Police saves us from damages within and yet the reaction of Government/Public is so apathetic towards our Policemen. Police-Public sammelens and introduction of model of community policing perhaps are the answer for image building and morale building of our uniformed Police Force.

Hence, it is upto the policy makers to let the Indian Police Force march forward with pride and dignity.

REFERENCES

1.Choudhary, R. (2009). Policing Reinvention Strategies In A Marketing Framework.

2.Deb, S., Chakraborty, T., Chatterjee, P., & Srivastava, N. (2005) Psychological Stress Of Traffic Police Officers, Causal Factors Behind The Same And Their Coping Strategies. The Indian Police Journal, LII (3), 16-30.

3.Dhillon, K.S. (1998). Defenders of the Establishment. Shimla: Indian Institute of

4.Eshwar Anand, V.(2009). Shortcuts won't do:States diluting SC fiat on police reforms.The Tribune, November7.

5.Khan S.A., & Bhandari A. (2006). The Police Edifice: Standing or Crumbling. New Delhi: Siddharth Publications.

6.Malik, M.S. (2004). Human Rights & The Security Forces. New Delhi: The Bright Law House, R.K. Offset Press.

7.Malik Sarita (2010). A study on Police Sub-Culture, Stress and Psychological well being.

8.Moon, B., & Zager L.J. (2007). Police officers' attitudes towards citizen support. Focus on individual, organizational and neighborhood characteristic factors. Policing: An International Journal of Police Strategies & Management, 30 (3), 484-497.

9.Philip, P.V. (1996). The Friends of the police movement in India. A Blueprint for Community Policing: In the Police Journal.

10.Raghavan, R.K. (1999). Policing a Democracy: A Comparative Study of India and the US, New Delhi: Manohar Publications.

11.Singh, S., & Singh, R. (2008). Towards People Friendly Police In India. The Indian Police Journal, LV (2), 28-35.

12.Tandon, U. (2007). Conceptualizing Human Rights of Police. The Indian Police Journal, LIV (2), 45-52.

13.Verma, A. (2000). Politicisation of the Police in India: Where lies the Blame?

14.Verma, A., & Gavirneni, S. (2006). Measuring police efficiency in India: An application of data envelopment analysis. Policing: An International Journal of Police Strategies & Management. 29 (1), 125-145.

*** saritamalik111@yahoo.co.in**

COMBATING HUMAN TRAFFICKING: REHABILITATION AND REPATRIATION OF TRAFFICKED VICTIMS

Dr. Neelam Arya,Ph.D.,M.C.A., LL.B. Senior Scientific Officer (SOC) Forensic Science Laboratory Haryana.*

Article published in 32th issue was emphasised on crucial role of forensic examination of trafficked victim. At the same time it is equally crucial of combating human trafficking and rehabilitation & repatriation of trafficked victims.

Extending the previous, The present Article identifies the issues, estimates complexities, various impediments, international instruments and conventions in combating trafficking and rehabilitation of victims and prosecution of offenders.

Successful economic rehabilitation of victims of trafficking does not merely mean livelihood generation, it is a composite process where the person feels psychologically, physically and economically tuned with the work environment and the larger world in which they are placed. The situation is alarming with inadequate efforts to combat and lower conviction, in most of cases traffickers go unpunished. Over the past decade, human trafficking revealed epidemic proportions. International laws are in place to fight this crime. The global initiative will analyse the problem from a wide range of geographical and thematic perspectives. As it can not be fought by individual countries or individuals, but by all countries. As many steps needed to be taken collectively to stall the growth of trafficking as in SAARC countries. The increasing exploitation of women and children from SAARC countries made SAARC countries to sit and ponder over the issue and find all measures which could be taken for the prevention as well as for repatriation and rehabilitation of trafficked victims. The convention obligates upon the state parties to provide sufficient means, training and assistance to their respective authorities to enable them to effectively conduct inquires, investigations and prosecution of offenders so as to prevent, control, combat and curb trafficking in person and the crimes related to it. If the Government is legally bound to ensure that every Child under 14 Years is in main stream School, then there must be complete Ban on Child Workers.

THE QUESTION IS NO LONGER: WHAT CAN BE DONE ABOUT HUMAN TRAFFICKING?
BUT
HOW WE CAN DO MORE AND DO IT BETTER.
THERE IS NO TIME TO LOSE OR WASTE

The supreme court of India very recently ordered both the central and state Governments to identify the sex workers willing to give up the trade in Delhi, Mumbai, Kolkatta and Chennai and suggests mode and manner of imparting vocational training to enable them earn a dignified livelihood. The court continued saying that it was taking up the exercise to give a chance to sex workers to live a life with dignity, a right guaranteed under Art. 21 of the Constitution. Question still remains, will they be accepted by their families, friends, society and all others or stigma will follow them like a shadow till they are alive?

One of the major problems faced is the repatriation of cross boarder victims to their country of origin. At present there are no streamlined procedures which would enable humane and quick repatriationof the victims. Repatriation calls for the support to cross boarder victims for their safe repatriation to their country of origin. It is too easy said than done. Although law has given ample powers to the police to enter and search without warrant and take appropriate actions in the given situation but due to lack fo sensitisition over burden of work on the part of police, legal provisions have remained on the statute book without its implementation in the letter and spirit.

Again supreme court of India has passed two very important judgements on the subject of rescue and rehabilitation programmes and the commercial exploitation of women and children in this country. Firstly in Vishal Jeet V Union of India, by Supreme Court observed that prostitution is not only a social but also a socio-economic problem and therefore, the measures that are to be taken in that regard should be more preventive than punitive. Secondly in the case of Gaura Jain V Union of India, where plight of prostitutes and fallen women in the flesh-trade and their progeny was highlighted. In this case the court was concerned more with the rehabilitation aspects than with prevention of the crime. The case of Prajwala V Union of India, came up before the apex Court in the form of Public Interest Litigation, wherein the question of protection of women has been raised in the context of Immoral Traffic[P]Act 15. The Apex Court showed concern for creating a monitoring agency to look on the activities of Protective Homes so that affected women may not go back to prostitution.

Human Trafficking is one of the most Severe Problems that exist in the modern day Society today, one that is desecrating the lives of Millions around the World. Although most of us have never witnessed this crime. It happens every day all around the world. However, although it may be severe does not mean that a Solution does not exist. Combating it requires a comprehensive international approach, through the Co-operation of the Public (by remaining Alert), Government, and Non-Governmental-Organizations (NGOs) we can all achieve what we cannot achieve by ourselves. We must act together to stop a crime in our midst that deprives countless victims of their liberty and dignity. Join the 21st century Anti-human Trafficking Initiative today. We can all make a difference.

* **drneealmarya@rediffmail.com**

सफलता के लिए जुनून बेहद जरूरी, उम्र कोई मायने नहीं रखती- केके सिन्धु

जीवन में सफलता के लिए जुनून का होना बेहद जरूरी है, उम्र कोई मायने नहीं रखती। यह उदगार हरियाणा पुलिस अकादमी के निदेशक श्री केके सिन्धु ने 31वीं मलेशियन इन्टरनेशनल ओपन मास्टर एथेलेटिक्स

चेम्पियनशिप (2017)में बेहतर प्रर्दशन करने वाले विजेता एसआई जितेन्द्र सिंह को उनकी सफलता पर बधाई देते हुए कहे। उन्होंने विजेता को प्रोत्साहन में पुन: मैडल पहनाते हुए कहा कि आज की युवा पीढ़ी को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि किसी भी कार्य के प्रति जुनून का होना अनिवार्य है। यदि जीवन मे किसी कार्य के प्रति जुनून है तो सफलता एक दिन आपको अवश्य मिलेगी। इसी जुनून,मेहनत व लगन के कारण ही एसआई जितेन्द्र लगातार गत तीन वर्षो से इस आयु वर्ग में चैम्पियन हैं। यह स्पर्धा 45 से 49 आयु वर्ग के प्रतिभागियों के लिए जुलाई माह में मेलेशिया में आयोजित की गई थी। जिनमें से हरियाणा पुलिस अकादमी के एसआई जितेन्द्र सिंह ने 1500 मीटर दौड में गोल्ड, 800 मीटर दौड में सिल्वर और 5000 मीटर दौड स्पर्धा में सिल्वर मैडल जीत कर हरियाणा पुलिस का ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष का नाम रोशन किया है।

Sports Achievement July to September -2017

World Police & Fire Games at Los Angeles,California USA from 07.08.2017 to 16.08.2017.

I. P/Inspr. Dinesh Kumar, (2nd Bn.) Gold

II.ORP/Inspr. Punit Rana, (3rd Bn.)- Gold Medal in 100 Mtr. BS & 50 Mtr. BS. Silver Medal in 200 Mtr. IM ,4*50 Mtr. FRM. Bronze Medal in 4*50 Mtr. MMR,4*50Mtr. MFR

III. L/ORP/Inspr. Nirmla, (GGM) KNL Gold

IV.L/P/SI Kavita Chahal (5th Bn) Gold

V.ORP/HC Sandeep No. 5/771 Gold

VI. L/ORP/HC Promila No. 2195/RTK, Gold

VII.L/EHC Santosh No. 1481/KNL Gold

Rajiv Gandhi Khel Ratan Award- P/DSP Sardara Singh Hockey player awarded on 29.08.17.

Gold Medelist Promila (Left) and Sandeep (Right) with Sh. KK Sindhu ,IPS DG/Dir. HPA & Sh. Subhash Yadav IPS, IGP Karnal Range

Light Vehicle Driving Course Batch No. 22 (16.06.2017 to 31.07.2017 extendeed upto 30.09.2017)

Courses

Two Weeks Course on "Anti Corruption" for DSsP & P/Insprs. (11 to 22.09.2017)

Three Days Advance Course on Mobile and Computer Foresnsic for NGO's & ORs (04. to 06.09.2017)

Heavy Vehicle Driving Course Batch No. 22 (16.06.2017 to 31.07.2017 extendeed upto 30.09.2017)

AWT & VIP Security Course Batch No. 62 (15.05.2017 to 13.07.2017)

Way to Police Public Interface

दयाल सिंह पब्लिक स्कूल करनाल व पानीपत के विद्यार्थियों ने क्रमश:2 व 3, 22 व 23 अग्रस्त 2017 को मधुबन पुलिस परिसर का भ्रमण किया और पुलिस संग्रहालय सहित पुलिस प्रशिक्षण सुविधाओं से परिचित हुए।

सर!ऑटोग्राफ प्लीज।

मैं भी सिपाही बनूँगा

भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम अनुभाग में बच्चों से संवाद

बम निरोधक दस्ते के तलाशी उपकरणों के प्रति जिज्ञासा

पदोन्नति एवं सेवानिवृत्ति के यादगार क्षण

श्री केके सिंधु भापुसे, निदेशक अकादमी बाएं व सशस्त्र पुलिस महानिरीक्षक श्री एचएस दून भापुसे दाएं व स्टाफ के साथ ग्रुप अवसर पर नव पदोन्नत पुलिस निरीक्षक वर्दी में निरीक्षक सुरेन्द्र कुमार, अंशुज सिंह, सतपाल सिंह, मेहर सिंह व कनुप्रिया

Sub. Sukhminder Pal

ASI Suresh Kumar

Sh. Jai Pal and Sh. Jitar Singh

Arrival and Joining at the Academy

Sh. Rajesh Kumar DA on 20.07.2017

Sh. Baljit Singh DDA on 07.07.2017

ASI Rakesh Kumar 166/GGM

Congratulations

Sh. B.S. Sandhu, IPS DGP Haryana has conveyed heartiest congratulations to all the police officers/ officials who have been awarded Police Medal on the eve of Independance Day 2017.

Gallantry Award (01)

Sh. Anil Kumar Rao IPS, IGP, CID, Haryana

Presidents' Police Medal for Distinguished Services (01)

Sh. Ajay Singhal IPS, ADGP/SVB,PKL, Haryana

Police Medals for Meritorious Services (10)

Sh. Alok Kumar Roy IPS, ADGP(Railways),PKL, Haryana

Sh. Y. Puran Kumar IPS DIG, CID,PKL, Haryana

Sh. Kirat Pal Singh IPS SP,SVB,Ambala

Sh. Shankuntla Devi HPS, DSP Karnal

Sh. Hissam Singh HPS, DSP Telecom, Panchkula

Sh. Raj Pal Singh Insp. Panchkula

Sh. Vijay Pal Insp. PTC Sunaria Rohtak

Insp. Azad Singh Bhiwani

SI Umed Singh Hisar

SI Vinod Kumar Ambala

ASI Mohan Singh Panchkula

Chief Editor : K.K. Sindhu, Director HPA ; Editors : Dr. Suman Manjri, IG/ HPA & SI Om Parkash (CPT Wing)
Page-making: C-1 Sewa Dass & Ct.Ram Kishan; Photo : HC Meenu Khan & Mr. Surender (Banti)